गन्ना किसानों व चीनी उद्योग को 5500 करोड़ का राहत पैकेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की समस्या सुलझाने और चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने 5500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। मिलें चीनी के भारी स्टॉक और आगामी पेराई सीजन में उत्पादन बढ़ने की संभावना के चलते नकदी संकट से परेशान हैं। किसानों के गन्ना भुगतान की समस्या और गंभीर हो जाने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने समय से पहले यह कदम उठाया है। राहत पैकेज में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, गन्ने की लागत भरपाई और चीनी निर्यात को सुगम बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

घरेलू बाजार में चीनी की बहुतायत के कारण इसकी कीमत लागत से भी कम पर चल रही हैं, जिससे उद्योग लगातार घाटे की ओर बढ़ रहा है। इससे उबारने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने कम से कम 50 लाख टन चीनी के निर्यात का फैसला किया है। इसके लिए मिलों को पर्याप्त मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यह फैसला लिया है। समिति ने बुधवार को खाद्य मंत्रालय के मसौदे पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे

कैबिनेट के फैसले

13000 करोड़ रुपये बकाया है गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर

चीनी के बढ़ते भारी स्टॉक और गन्ना किसानों के बढ़ते बकाए के भुगतान में राहत मिल सकती है। मिलों पर फिलहाल 13000 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का बकाया है।

कुछ राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव और फिर अगले वर्ष संसदीय चुनाव के मद्देनजर सरकार का यह फैसला अहम होगा। गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को राहत देने के लिए सालभर के भीतर यह दूसरा राहत पैकेज है। सरकार के राहत पैकेज में आगामी पेराई सीजन में किसानों को गन्ने के मूल्य के रूप में 13.88 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।

Dainik Jagran.
27-09-18.